(ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन-भूमि को उपयोग में लाने की मंजूरी देते समय बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में पूर्ण जलाशय स्तर से 4 मीटर नीचे तक डूब में आने की संभावना वाले क्षेत्र से पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वृक्षारोपण कार्यक्रम

4566. **श्री शिव प्रसाद बनपुरिया:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वृक्षारोपण-कार्यक्रम पर मवेशियों की चराई का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) वृक्षारोपण को मवेशियों की चराई से अब तक कितना नुकसान हुआ है और क्या वन-विभाग द्वारा इस संबंध में कोई आकलन किया गया है;

(ग) इस नुकसान से बचने के लिये वन विभाग द्वारा क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं ; और

(घ) क्या इस संबंध में वनों के निकटवर्ती गांवों में बकरी-पालन पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) अनियमित चराई से वनीकरण कार्यकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(ख) अनियमित चराई से वृक्षारोपण को पहुंची क्षति की सीमा प्रत्येक राज्य में अलग-अलग है जोकि गांवों में पशुओं की संख्या तथा चरने के लिए बाहर से आने वाले पशुओं की संख्या पर निर्भर करती है। चराई के कारण वृक्षारोपण को पहुंची क्षति की सीमा ठीक-ठीक निर्धारित करने के लिए कोई अखिल भारतीय मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(ग) राज्य वन विभाग रोपण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की बाड़ लगाकर और पशु-रोधी खंदकें खोद कर उन्हें चराई से पहुंचने वाली क्षति से बचाने का प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त, जिन क्षेत्रों में वनों का विनाश हुआ है उनकी सुरक्षा में ग्रामीण लोगों को इस आधार पर शामिल किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं कि जिन क्षेत्रों की सुरक्षा और विकास करने में वे सहमत होंगे उससे प्राप्त होने वाली वनोपज पर उनका भी अधिकार होगा।

(घ) जी, नहीं।

देश में वनों में वृक्षों की अवैध रूप से कटाई

4567. **श्री शिवचरण सिंह:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वन विभाग को वृक्षों की कटाई का अधिकार दे दिया गया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में वन विभाग लकड़ी काट कर उसे वन उत्पाद के रूप में बेचते हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह विभाग सवाई माधोपुर के वन रेंज तथा मडरापल, मोसलपुर और धौलपुर के वन विहार तथा राम सागर और झिरी वन से लकड़ी काट कर उसे ऊंटों की मदद से ले जाता है अथवा वहां से लकड़ी/इमारती लकड़ी चोरी-छिपे ले जायी जाती है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या इस संबंध में मौके पर कोई जांच कराये जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) राज्य वन विभागों को ये अधिकार दिए गए हैं कि वे कार्यकारी योजनाओं/प्रबंध योजनाओं के तहत अनुमोदित

वनवृक्ष विज्ञान की अपेक्षाओं के अनुसार लोगों की ईंधन, इमारती लकड़ी एवं गैर-काष्ठ वन उत्पादों संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वृक्षों की कटाई कर सकें।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

Environmental Progamme

4568. SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN :
SHRI J.S. RAJU :
SHRI MISA R. GANESAN :

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state :

(a) what are the environmental programmes envisaged by Government of India for the near future to project the welfare pf the society at large;

(b) what is the responsibility of the State Governments in the application of these environmental programmes; and

(c) what is the total amount spent so far on environmental programmes for the years 1990, 1991, 1992 and 1993 ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FOREST (SHRI KAMAL NATH) : (a) and (b) Names of the major environmental programmes envisaged by the Govemment of India for the near future to project the welfare of the society at large alongwith responsibility of the State Governments in the application of these environmental programmes are given in the enclosed Statement (*See* below).

(c) Total amount spent so far on environmental programmes for the last four years is given below :

(Rs. Crore)

1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
44.39	34.60	45.10	69.00 (Anticipated)

Statement

Sl. No.	Name of the Environmental Programme	Responsibility of State Government in the implementation of programme
1	2	3
1.	Environmental Information System	Central Sector Scheme. The implementation of the scheme does not involve State Governments.
2.	Centres of Excellence	—do—
3.	National Natural Resource Management System	—do—
4.	Assistance to Botanic Garden and Field Centres	The concerned State Governments are responsible for implementation of the programme in case programme is sanctioned to them.
5.	Biodiversity Conservation	—do—
6.	Awareness Planning for Emergencies at the Locale level	The concerned State Governments have a major role in creating awareness and planning at a local level.